made a request to the hon. Member, and I would suggest that this Bill need not be introduced.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): Let him ask for leave to introduce the Bill and then the Minister can object. When there is no business before the House, the hon. Minister cannot get up and object.

MR. SPEAKER: There is nothing wrong if the hon. Member does not get up after listening to the hon. Minister.

SHRI AMAR NATH CHAWLA (Delhi Sadar): In view of the assurance of the hon. Minister, I do not move the motion.

11.32 hrs.

FREEDOM FIGHTERS (APPRECIATION OF SERVICES) BILL

By *Prof. Shibban Lal Saksena*—contd.

MR. SPEAKER: The time allotted for this Bill is 2½ hours, we have already taken 2 hours and 4 minutes. Shri Jharkande Rai may continue his speech.

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाये। मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार कर लें ताकि विचार-विनिमय के दौरान सारी बातें आ जायें। माननीय सदस्य भी अपना विचार प्रकट करना चाहेंगे। अगर सेलेक्ट कमेटी में यह जायेगा तो इस का मौका मिल जायेगा। मैं नहीं समझता कि कोई भी इस के सिद्धान्त का विरोधी होगा।

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): सिद्धांत से हमें कोई विरोध नहीं है। हम सब कुछ जानते हैं और हाउस की राय भी हम को मालूम है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : क्या और राय आने से बदहजमी हो जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री मिश्र से कहना चाहता हूं कि बदहजमी शब्द अनपार्लियामेंट्री तो नहीं है, लेकिन इस का इस्तेमाल बहुत दुरुस्त नहीं मालूम होता।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अगर वह अंग्रेजी में इनडाइजेस्शन कहते तब इस को आप बुरा न कहते।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं नहीं मानता कि इस में कोई बुरी बात है।

SHRI F. H. MOHSIN: We know the intention of the whole House. People from both sides of the House have spoken. Not that we are unaware of the feelings of the members. It is not necessary that it should go to a select committee.

SHRI R. S. PANDEY (Rajnandgaon): I support Mr. Vajpayee's suggestion. If it goes to the select committee, some comprehensive recommendation may come out of it. Otherwise, it is a private member's Bill and its fate is well known. It will be defeated.

SHRI R.V. SWAMINATHAN (Madurai): I agree with Mr. Pandey.

MR. SPEAKER: But there is no substitute motion for referring it to a select committee.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I will move it now. You can waive the rule. This is an emergency period.

SHRI F. H. MOHSIN: I do not want it to be defeated. I would request him to withdraw his Bill.

MR. SPEAKER: Are you in a position to accept the Bill or not?

SHRI F.H. MOHSIN: We basically accept the intention behind the Bill.

MR. SPEAKER: If you are going to oppose this Bill, we can ignore the suggestion about select committee.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): Let the minister intervene now, so that the other speakers may have the benefit of knowing the mind of the Government.

MR. SPEAKER: Once I call on the minister to speak, I will not be able to allow any other speaker.

SHRI SAMAR GUHA (Contai): The whole House has expressed almost unanimous opinion that the spirit of the Bill should be carried out. Here and there certain changes may be necessary For that, the suggestion of Mr Vajpayee may be accepted The difficulty is, if the minister says he will not accept it, the Bill will fall through.

MR SPEAKER: He has already indicated it. If you want, we can have more time for this Bill.

How much time do you want?

SOME HON. MEMBERS Two hours more.

MR. SPEAKER. All right,; two hours more

Shri Jharkhande Rao to continue his speech

श्री झारखंडे राय (घोसी): मै पिछली बार कह रहा था कि हिन्दुस्तान की पहली आजादी के सब से बड़े सिपाही हवलदार बहादुर शाह जफर की कब्र रंगून के पास बियाबान जंगल मे बनी हुई है। उसके सामने नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने प्रतिज्ञा की थी कि जब भारत स्वतन्त्र होगा तो उसकी मिट्टी स-सम्मान भारत लाई जाएगी और लाल किले मे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसको दफनाया जाएगा। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हू कि नेता जी की उस प्रतिज्ञा को वह पूरा करे।

उसी तरह से नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने अंदमान के पोर्ट ब्लेयर जेल के सामने आ कर 1943 मे इस बात की प्रतिज्ञा की थी कि जब हिन्दुस्तान आजाद होगा तो पोर्ट ब्लेयर मे शहीदों का एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाएगा, उस जेल को तोड़ कर वह शहीद-स्मारक बनाया जायगा। हिन्दुस्तान के चुने हुए सैकड़ो शानदार क्रान्तिकारी, तपस्वी, त्यागी और स्वतन्त्रता के सेनानी वहां बन्दी रहे हैं और तरह-तरह की यातनायें उनको सहन करनी पड़ी हैं। मैं चाहता हूं कि नेताजी की उस प्रतिज्ञा को भी भारत सरकार को पूरा करना चाहिये। स्वतन्त्रता की खातिर मर मिटने वाले एक महान देशभक्त ने, एक महान क्रान्तिकारी ने जो प्रतिज्ञा की थी, उसको पूरा किया जाना चाहिये।

इसी तरह से 1908 मे वीर सावरकर के एक प्रमुख शिष्य मदन लाल ढींगरा ने लन्दन मे कर्नल वाइली का वध किया था जोकि हिन्दुस्तान के विद्यार्थियों और अन्य क्रान्तिकारी युवको पर खुफिया-गिरी किया करते थे। ऐसा वध करके ढींगरा ने उचित ही किया था। उनकी कब्र लन्दन मे बनी है। उस पर एक पत्थर है, जिस पर लिखा है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हिन्दुस्तान के विद्यार्थी और नौजवान हमारी मिट्टी को हिन्दुस्तान ले जाएंगे। मैं चाहता हू कि उस भावना का भी आदर किया जाए।

दिल्ली मे कुछ दिन पहले एक पुराना सैंट्रल जेल था। उसको तोड कर आज आजाद मेडिकल कालेज उसी स्थान पर बना दिया गया है। उसके विषय मे हिन्दुस्तान के सभी क्रान्तिकारियों ने एक सम्मेलन मे इस बात की माग की थी कि उस जेल को क्रान्तिकारियो के मैमारियल की शक्ल दे दी जाए, एक शहीद स्मारक वहा बनाया जाए। लेकिन सरकार ने उस समय, जब गृह मंत्री पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त थे, इसको स्वीकार नही किया था। इसके बाद क्रान्तिकारी सम्मेलन की ओर से यह माग रखी गई थी कि मैडीकल कालेज अगर बनता है तो उसके मुख्य गेट के सामने एक स्मारक बनाया जाय क्रान्तिकारी शहीदो का। लेकिन भारत सरकार ने उसको भी ठुकरा दिया। यह उस समय की क्रान्तिकारी विरोधी प्रवृत्ति का परिचायक है।

दिल्ली मे 1912 मे लार्ड हार्डिग के हाथी पर रास बिहारी बोस के नेतृत्व मे बम फेंका गया था। यह उस समय हुआ था जब लार्ड हार्डिग कलकत्ता के बाद दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप मे बदलने के बाद शानदार तरीके से जलूस मे चल रहे थे, और उसका विरोध भारतीय क्रान्तिकारियो की तरफ से किया गया था। उस षडयन्त्र मे तीन क्रान्तिकारियो को फांसी दी गई थी। वे थे मास्टर अमी चन्द, बाल मुकुन्द और अवध बिहारी। ये तीन क्रान्तिकारी उसी जेल मे रहे और उनको वहीं फांसी भी दी गई थी।

सरदार भगत सिंह को कौन नही जानता? जहां हम बैठे हुए है यह वही स्थान है जहा अंग्रेजी-दासता युग में सैंट्रल असेम्बली हुआ करती थीं। यहीं पर भगतसिंह और बटुकेश्वर ने बम फेंका था। वह एक ऐतिहासिक दिन था। वह कार्य ऐतिहासिक पुरुष द्वारा किया गया था और ऐतिहासिक स्थान पर किया-

गया था। उन दोनो को भी उसी दिल्ली सैन्ट्रल जेल में बन्द किया गया था। इन सब बातो को देखते हुए उन शहीदो का आदर किया जाना चाहिये। देर से ही सही, लेकिन अब भी समय है जब हम उनकी भावनाओ का आदर कर सकते हैं। आजाद मेडिकल कालेज के सामने एक शानदार प्रस्तर मूर्ति या किसी और प्रकार का कोई स्मारक शहीदो की याद मे बनाया जाय।

इस बिल मे श्री सक्सेना ने जो सुझाव तरमीम की शक्ल मे दिए हैं, उनका मैं समर्थन करता हू, एक बात को छोडकर। उन्होने स्वतन्त्रता सैनिको को जमीन देने की बात कही है। उसका मैं विरोधी तो नही हू लेकिन उस मे मैं यह तरमीम करना चाहता हू कि जिन स्वतन्त्रता सेनानियो के पास जमीन है या उनके परिवार वालो के पास जमीन है, उनको जमीन हरगिज न दी जाए। मैं भी स्वतन्त्रता सेनानी रहा हू। लेकिन मेरे पास घर की जमीन है। मुझे क्या जमीन दी जाए? केवल जो बेजमीन हैं या जिनके पास अलाभकर जोत हैं, उनको जमीन दी जाय। बाकी जो सुविधायें है तरमीम की शक्ल मे पेश की गई हैं, वे दी जाये और उनका मैं समर्थन करता हू।

आजाद हिन्द फौज वाले भी स्वतन्त्रता सेनानी रह चुके हैं। उस मे हिस्सा लेने के लिए जो जीवित है या जो मर गए है, उनके परिवार वाले हैं, उनको भी हर तरह से वही सुविधाये मिलनी चाहियें जो अन्य आजादी के सेनानियो को मिल रही हैं या मिलेगी। इसी प्रकार आर.आई.एन. यानी जिन लोगो ने 1946 फरवरी मे हिन्दुस्तानी नवी मे बगावत की थी, उनको भी ये सुविधाये मिलनी चाहिये। 18 फरवरी, 1946 को उन्होने बगावत की थी और उसकी वजह से ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जडे हिल गई थी। वह आखिरी ठोकर थी। 21 फरवरी को 72 घटे के भीतर ब्रिटिश पार्लियामेंट मे घोषणा हुई थी कि हिन्दुस्तान से समझौते की बातचीत करने के लिए सर स्टेफर्ड क्रिप्स की रहनुमाई मे एक मिशन भारत जाएगा। बगावत के ठीक 72 घटे मे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की चूले हिल गई। उन लोगों को भी आजादी के लिए लडने वाले सिपाही माना जाए। जो जीवित हैं उनको और जो मर चुके हैं उनके आश्रितो को भी ये तमाम सुविधायें दी जानी चाहियें।

इस विषय मे हिंसा, अहिंसा, क्रान्तिकारी गैर-क्रान्तिकारी कांग्रेसी या गैर-कांग्रेसी आदि का कोई भेदभाव नही होना चाहिये। जंगे आजादी सब ने एक ही मकसद के लिए लडी और वह था कि हिन्दुस्तान आजाद हो। कई लोगो ने क्रान्तिकारी रास्ता अपना कर अपने तौर पर इसका प्रयास किया। अनेको ने कांग्रेस और गांधी जी का रास्ता पकडा। बहुतो ने नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के रास्ते को पसन्द किया। मुख्यतया भारत मे तीन रास्ते अपनाये गये। सब का लक्ष्य एक था। वह यही कि हिन्दुस्तान को पूर्ण स्वतन्त्रता मिले। इस वास्ते इन मे किसी प्रकार का कोई भेद हर्गिज नही होना चाहिये। यह बात मैं बल दे कर कहना चाहता हू।

कुछ और मामले हैं जिनको मै सरकार के सामने लाना चाहता हू। उन मे से कुछ लज्जाजनक बातें भी हैं। श्री चन्द्र सिंह गढवाली को कौन नही जानता। वह ऐतिहासिक पुरुष हैं। पेशावर मे, खां अब्दुल गफ्फार खां के क्षेत्र मे, 1930 मे गोली कांड हुआ था जिस ने सारे हिन्दुस्तान को हिला दिया था और इसलिये जलियांवाला बाग के बाद भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास मे इसका नम्बर आता है। उस मे चन्द्र सिंह गढवाली ने, जब उनको जनता और प्रदर्शनकारियो को शूट करने का हुक्म दिया गया तो उन्होने और उनकी टुकडी ने शूट करने मे इन्कार कर दिया था। उस वीर चन्द्र सिंह गढवाली को जो पेंशन अब दी जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या केन्द्र की तरफ से, वह इतनी कम है कि लज्जा आती है उसको देख कर, घृणा होती है। ऐसे वीर सेनानी की महात्मा गांधी ने प्रशंसा की थी और उनका समर्थन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऐसे ऐतिहासिक पुरुष को जो सहायता दी गई है वह नगण्य है। उसको सुधारने की आवश्यकता है। पूरी सहायता उनको और उनके आश्रितो को दी जानी चाहिये।

इलाहाबाद मे अल्फरेड पार्क का नाम बदल कर मोतीलाल नेहरू पार्क कर दिया गया है। यह वह स्थान है जहा 27 फरवरी, 1931 को क्रान्तिकारी सेनानी चन्द्र शेखर आजाद ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद की पुलिस से आमने-सामने मुकाबला किया था। हिन्दुस्तान की आजादी की लडाई में बहुत कम क्रान्तिकारी ऐसे हुए हैं जिन्होने इस तरह से आमने-सामने मुकाबला करके अपने आपको कुर्बान किया हो। उसके नाम पर इस पार्क का नाम आजाद पार्क रखा जाना चाहिये। पं० मोती लाल नेहरू का मैं भी भक्त हूं। उनके नाम पर हिन्दुस्तान में हजारो स्थान की चीजें बनी

[श्री झारखण्डे राय]

हुई है। उपरोक्त मांग वहा की जनता ने की थी। इस बारे मे उदारता का भाव दिखाना चाहिये और उस पार्क का नाम आजाद पार्क रखा जाना चाहिये ताकि क्रान्तिकारी-स्मृति बनी रह सके।

मैं यह भी चाहता हू कि स्वतन्त्रता सेनानी चाहे हवालात मे रहे हो, सजा याफ्ता रहे हो या फरारो की तरह से रहे हो, सब का बिना भेदभाव के स्वतन्त्रता सैनिक माना जाना चाहिये। ऐसा नही होना चाहिये कि जो जेल गए हो या जिन को सजा हो गई है, ऐसे लोगो को ही इस श्रेणी मे रखा जाए। जिन का सजा नही हुई और सजा होने से पहले ही वे किसी कारण से छोड दिये गए हैं, उनको भी इस श्रेणी मे शामिल किया जाना चाहिये।

अगस्त, 1942 मे जो विद्रोह हुआ था उस मे हमारे उत्तर प्रदेश के एक नौजवान को फासी पर लटका दिया गया था। उनका नाम श्री राज नारायण मिश्र था। यह मेरे साथी थे और हम एक साथ लखनऊ जिला जेल मे थे। साथी राजनारायण मिश्र को 9 दिसम्बर, 1944 को फासी दी गई थी। मैं भी उस समय उसी जेल मे बन्द था। उनके दो बच्चो और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विद्यावती देवी के साथ आज जो व्यवहार किया जा रहा है केन्द्र या राज्य सरकार की ओर से वह तिरस्कार योग्य है। उसको देखकर गुस्सा आता है। दुख होता है। ऐसे लोगो के त्याग और बलिदान की वजह से ही आज हम को यह स्वतन्त्रता का दिन देखने को मिला है। उनका समुचित आदर होना चाहिये।

जो व्यक्ति स्वतन्त्रता-सेनानी रहा है, उस को, अथवा उस की पत्नी या पुत्र-पुत्री को या पूर्णतया आश्रित व्यक्तियों को तब तक सहायता देनी चाहिए, जब तक वे जीवित रहे या जब तक वे स्वावलम्बी न हो जायें।

1857 का स्वतन्त्रता-संग्राम हमारी पहली जंगे-आजादी थी। उस समय बहुत से देश-द्रोहियो को बडी बडी जमीने, रियासते और इनाम दिये गये थे। आज उन के वंशज हिन्दुस्तान मे बहुत आदर के स्थानो पर भी हैं और ऐसे कुछ लोग कुछ दलो मे हैं। अगर हिन्दुस्तान भर के मंत्रियो की लिस्ट देखी जाये, तो मुमकिन है कि उन मे ऐसे लोग हो जिन के बाप-दादाओं ने 1857 की जंगे-आजादी में गद्दारी की थी। ऐसे लोगो से तमाम जमीनें, रियासतें और इनाम वापिस लिये जाने चाहिए और उनका बटवारा स्वतंत्रता सैनिको मे कर दिया जाय। ऐसा न करने का अर्थ होगा कि सरकार गद्दारो की हिफाजत करना चाहती है।

यू०पी०, गोरखपुर मे सरदार नगर मे सरदार साहब (सुन्दर सिंह मजीठिया) की दो फैक्टरीज और एक फार्म हैं। इन के बाप-दादाओ ने 1857 मे गद्दारी की थी। बागी राजाओ की रियासते छीन छीन कर ऐसे लोगो को उन दिनो दी गई थी। उन को वापिस लेना चाहिए। हिन्दुस्तान भर मे ऐसी जो जमीने आदि हैं, वे वापस ले कर देशभक्तो को दी जायें।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ अच्छा काम किया है। वहा पहले स्वतन्त्रता सैनिको को 20 से 65 रुपये तक पेन्शन दी जाती थी। श्री कमलापति त्रिपाठी की मौजूदा सरकार ने उस पेन्शन की धनराशि बढा कर 60 से 100 रुपये तक कर दी है। मैं इस की तारीफ करता हू। लेकिन, जैसा कि इस बिल मे कहा गया है, किसी आजादी के सिपाही को भी 100 रुपये मासिक से कम न दिया जाये।

पश्चिमी बगाल की युनाइटिड फ्रंट गवर्नमेंट ने कई स्क्वेयर्ज, चौराहो और पार्कों आदि का नाम परिवर्तित कर के हिन्दुस्तान की जंगे-आजादी के सिपाह-सालारो और पुराने क्रान्तिकारियो के नाम पर रख दिया है। कलकत्ता मे डलहौजी स्क्वायर एक मशहूर जगह है। उस का नाम बदल कर उन तीन युवको के नाम पर, जिन्होंने इन्स्पेक्टर-जनरल आफ जेल, कर्नल सिम्पसन, को गोली से मारा था, विनय-बादल-दिनेश चौराह रख दिया है। उसी तरह से, सारे भारत मे जितने भी ऐसे स्थान हो, जो अंग्रेजो के नाम पर हैं, उन के नाम बदल कर हिन्दुस्तान की आजादी की लडाई लडने वालो के नाम पर रखे जाने चाहियें, चाहे वे क्रान्तिकारी रहे हो, कांग्रेसी रहे हो या सुभाषचन्द्र बोस के साथ काम करने वाले रहे हो।

इस बिल की मूल आत्मा का ही समर्थन नही किया जाना चाहिए, बल्कि व्यावहारिक रूप से इसका समर्थन करना चाहिए, और ठोस कदम उठा कर हमारे स्वतन्त्रता-सेनानियो को आर्थिक सहायता देनी चाहिए और इस प्रकार उन लोगों या उन के आश्रितों को अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर दिया जाये।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

SHRI N. K. P. SALVE (Betul) : On a point of information, Sir. Are you admitting the Motion by waiving the rules? Are you admitting the Motion for constituting a Select Committee?

MR SPEAKER: That is too late.

SHRI N. K. P. SALVE : May I know, Sir, are you admitting or not, by waiving the rules?

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: There is demand for this from the other side of the House also; the House unanimous.

SHRI N. K. P. SALVF: If you admit, I have a suggestion to make on this. This Minister has admitted, without disclosing his mmd...

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore). How can he admit, without disclosing his mind?

SHRI N. K. P. SALVE : That is on the assumption that my hon. friend has won and on the assumption that the hon. Minister has a mind. Anyone who has a mind will always be with the spirit of the Bill. So, I would like to come forward with this suggestion. If the hon. Minister could assure us that Government will bring forward a measure of their own accord, then in that case, it will be a very amicable settlement. Otherwise, we are likely to be put in an embarrassing predicament on the motion of Shri Atal Bihari Bajpayee, because for long we have paid lip-service to our martyrs and it is time that we do something to them...

MR. SPEAKER: I did not allow him to speak.

SHRI N. K. P. SALVE: It is not a speech, but it is a sensible suggestion, and sometimes you should entertain some sensible suggestions also.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे अपना संशोधन पेश करने की इजाजत दें ।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: It is the unanimous wish of the House. It is the unanimous request of the House.

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इजाजत दे देता हूं, लेकिन इससे आपको क्या कानसोलेशन होगा ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : शायद अब भी मंत्री महोदय बुद्धिमत्ता से काम लें ।

अध्यक्ष महोदय : दोनों तरफ बुद्धिमत्ता से काम लें ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह अब इन्कार नहीं कर रहे हैं । वह फिर से विचार कर रहे हैं ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : ऐसी बात नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : उनकी "हां" में भी इन्कार है ।

What is the consensus of the House?

SEVERAL HON. MEMBERS: Notice may be waived.

MR. SPFAKER: The consensus is that this motion should also be discussed along with the motion for consideration. All right, let it also be moved. But what consolation will the Hon. Member get out of this? The Hon. Minister is not accepting it.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे अपना संशोधन पेश करने दीजिए । नामों के बारे में मेरा आग्रह नहीं है । मंत्री महोदय जो भी नाम बतायेंगे, हमें उन पर ऐतराज नहीं होगा ।

MR SPFAKFR: The Hon. Minister is not agreeable to any proposal for a Select Committee.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप रूल को वेव कर दीजिए । तब सदन के सामने मेरा संशोधन आ जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कर दिया है – कान्सेन्सस लेकर कर दिया है । अगर इससे आपको तसल्ली होती है, तो मुझे क्या एतराज होगा ? लेकिन अपने अमेंडमेंट को डिफ़ीट कराकर आपको क्या तसल्ली होगी ?

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदय, जब मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा

[डा० गोविन्द दास सेठ]

हुआ, तो मुझसे पहले जो महाशय अपना भाषण कर रहे थे, आपने उनको समय दिया। वह बिल्कुल उचित बात थी। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं इस मामले में बरसों से सरकार के साथ बात कर रहा हूं, लड़ाई तक कर रहा हूं।

12 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मैं समझता हूं कि आजादी मिलने के बाद दो युग बीत जाने पर भी हमने और हमारी सरकार ने इस सम्बन्ध मे कुछ नही किया है। कुछ प्रान्तो मे जरूर काम हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश की बात हमने सुनी। मैं मध्य प्रदेश से आता हू। वहा भी कुछ काम हुआ है। लेकिन जो काम हुए हैं, वे अलग अलग तरह के हैं। किसी प्रान्त में किसी तरह का काम हुआ है और किसी प्रान्त में किसी तरह का। किसी प्रान्त मे सतोषजनक काम हुआ है और किसी मे असतोषजनक काम हुआ है।

यह प्रश्न प्रान्त का प्रश्न नही है। यह प्रश्न अखिल भारतीय प्रश्न है और सचमुच में यह खेद की बात है कि इतना समय बीत जाने पर भी भारत सरकार ने सम्पूर्ण भारत को दृष्टि मे रखकर इस सबध मे अब तक कुछ नही किया। सन् 1914 और 1939 के युद्धो का हमने बहिष्कार किया था लेकिन आज भी जिन लोगो ने सन् 1914 और 1939 के युद्धो मे भाग लिया उनको पेंशन दी जाती है। स्वराज्य के बाद उन पेंशनो को तत्काल बन्द किया जाना चाहिए था। यह बात नही की गई और आज तक उन लोगो को पेंशन मिलती है। जहां तक स्वतत्रता सग्राम के सैनिको का सबध है दो प्रश्न आपके सामने हैं। एक प्रश्न है उनके सम्मान का और उस सबध में हम जो कुछ कर सकते हैं वह हमें करना चाहिए। अभी तक हमने नही किया है। दूसरा प्रश्न है उनको आर्थिक सहायता देने का। इस सबध में भी हमे जो कुछ करना चाहिए वह हमने नही किया है। इसीलिए श्री शिब्बन लाल जी सक्सेना का जो विधेयक है और उस पर उनके जो सुझाव हैं उन सबका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। जहा तक सरकार का मामला है हमारे मत्री जी ने इस बात को तो स्वीकार किया कि इस सबध मे सारे सदन की एक राय है और उस राय से वह सहानुभूति रखते हैं। लेकिन सहानुभूति रखने से तो काम नही चलेगा। सहानुभूति रखते हुए तो उनको आज 24 वर्ष बीत गए और 24 वर्षों के बाद भी प्रश्न वैसे का वैसा जटक रहा है जैसे आज से पहले अटक रहा था। एक प्रश्न यहां पर यह भी आया कि देश की राय के लिए भेज दिया जाय। यह बड़ा गलत प्रश्न है। मैं कहना चाहता हू जिन विधेयको को हम खत्म कर देना चाहते हैं उनको इस प्रकार से पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजा जाता है। जहां तक सेलेक्ट कमेटी का मामला है मैं बहुत दूर तक वाजपेयी जी से सहमत हूं। मेरा खुद का यह कहना है कि इतने प्रश्न इसके अतर्गत हैं कि इस सारे सदन मे इस बिल मे इसी रूप मे कुछ कर सकना सभव नही होगा। इस लिए इसके लिए एक सेलेक्ट कमेटी बना दी जाती है और यह विधेयक तथा उसके सबध मे सुझाव उस सेलेक्ट कमेटी के सामने भेज दिए जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। सेलेक्ट कमेटी में पूरे तौर पर ब्यौरे में इस सारे की जाच हम लोग करेंगे और जाच करने के बाद इस सबध में कुछ कर सकेंगे।

इस सबध में यहां पर एक बात और कही गई, साल्वे साहब ने कहा कि अगर सरकार स्वय इस प्रकार का कोई विधेयक ले आए सब बातों पर विचार करके, जो कुछ सदन में कहा गया है, जो कुछ सदन के बाहर कहा गया है उन सब बातो पर विचार करके एक ब्यौरेवार विधेयक सरकार ले आए तो जिन्होने यह विधेयक पेश किया है, सक्सेना साहब ने, उनसे मैं कहूंगा कि वह इसको वापस ले लें। सरकार यदि इस प्रकार का वादा करती है और यह वादा करती है कि अगले अधिवेशन मे यह विधेयक वह ले आएगी तो सक्सेना साहब को इस सबध मे कोई आपत्ति नही होनी चाहिए कि वह अपने विधेयक को वापस ले लें। इस प्रश्न को लटकते हुए काफी समय बीत गया है। सरकार इस सबध मे कुछ नही कर सकी है। जिन प्रान्तो मे कुछ हुआ है वहा भी अधूरा हुआ है। दो प्रश्न इसके साथ मे हैं। पहला तो यह कि स्वतत्रता संग्राम के सैनिको का हम उचित सम्मान करें और दूसरा यह कि उनको और उनके कुटुम्ब की आर्थिक सहायता करें। इन दोनो पर विचार करके सरकार इस सबंध मे कोई विधेयक रखना चाहती है तो माननीय मत्री जी इस बात का आश्वासन दें कि अगले अधिवेशन मे यह विधेयक आएगा। उस समय सक्सेना साहब इस विधेयक को वापस ले लेंगे। या फिर जैसा वाजपेयी जी ने कहा इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज देना चाहिए। अगर यह दोनो बातें नही होती तो यह एक दूसरा अनर्थ होगा कि एक विधेयक इतने दिनो के बाद बड़ी मुश्किल से गैरसरकारी सदस्य की तरफ से आया भी तो उसको भी हम इस तरह से जाने दें। इसलिए इस विधेयक का और इन सुझावों का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar): Sir, since the last one

year, our country is undergoing changes in many spheres, and it has become a year of victories and on the 16th December, 1971, that is yesterday, India emerged as one of the great liberating forces in the Asian horizon. Today, when we pay glorious tribute to the valiant freedom-fighters of Bangala Desh and all the other freedom-fighters and the brave armed forces of our country, this is a great moment which brings to our mind the sufferings and privations of all our freedom-fighters of earlier years, in all the liberation struggles which were carried out for achieving our own independence in 1920-21, 1930-31, and in 1942 days. There was also the great naval muntiny which took place just before the independence of our country and also great fight which was carried on by the INA soldiers, under the command of Netaji, who fought for India's independence.

Besides these, there were other liberation struggles which were carried on in the ex-State areas, those princely States. In Orissa, we had one of the biggest struggles in the Ranpur State; because of the provocation and oppression of the British political agent Bazdgette he was murdered and then a reign of terror was let loose on the people of Ranpur. Raghu, Dibakar were executed and many more got life-terms of sentence. Many of the people were fighting in the ex-State areas like the people of Thuabari village in the district of Puri. A proper history of those struggles has not been maintained. But the fact remains that in those days great struggles were waged by those people who were engaged in what was called the States People's movement in those days. The fights in the States of Dhenkanal, Talcher, Ranpur, Daspalla, Nayagarh and Nilgiri and other regions, the ex-State areas, were heroic and the memories of oppression let loose on the fighters and the people strike horror in the minds of the people of Orissa even to this day. We are grateful to the country, and to the Government, that at last, after many years, the ex-rulers of princely States were divested of their powers and the princes were deprived of their purses and privilegs and thus we have put an end to those evils perpetrated by those ex-Rulers.

Here, I may bring to the notice of the hon.Minister that Prof. Saksena has brought a Bill to which we all agree in its principles, and the hon.Minister has made it very clear that the Government is in no different mind as regards the spirit of this Bill. We all agree with the principles of the Bill. The Government of India, in fact, have gone a little out of the way to help the political sufferers; that is, where the State Governments have not been able to help them, the Government of India, in the Ministry of Home Affairs, have gone out of the way to help at least from their own funds, whenever the occasion arises and whichever case came to their notice, those political sufferers, freedom-fighters, to relieve them from their abject poverty and suffering. Therefore, there is no different mind on this score, so far as the Government of India and the Congress Party, is concerned.

Now, take the case of the Orissa Government. They are paying only Rs. 30 to Rs. 40 each as pension to the political sufferers who fought for the independence of the country. Again, it so happened that this pension became subject of political discrimination also. That is to say, suddenly, when a different Ministry came—not the Congress Government — the pension of almost a thousand of them was suspended. Even this Rs. 30 as pension was suspended. Therefore, it is better that the Central Government really comes forward with a kind of comprehensive Bill in this matter for providing the freedom-fighters with a suitable amount of pension in the entire country.

We are aware that the Prime Minister has declared that India is going to celebrate the 25th year of its independence next year, and the celebration of the 25th year of independence next year assumes greater importance because India has already become a liberating force in the whole of Asia, in this sub-continent. Therefore,

[Shri Chintamani Panigrahi]

I hope that proper consideration which is due to those freedom-fighters, who had laid down their lives to achieve independence, and those who have suffered in many ways for achieving independence so that today a strong and independent India has ultimately risen to this height in 1971, will be given to them at this hour.

I would submit to the hon. Minister that so far as this pension which is given to the ex-prisoners in the cellular jail in the Andamans is concerned,—there are about 20 in Orissa—they should get it. The Government of India issued some advertisement in the newspapers saying that the political sufferers should apply for pension. These freedom-fighters are living in remote villages. We have tried our best to contact some of them, and have pointed out that an advertisement has come and therefore they must apply If some of them are not able to apply in time in Orissa, I request the Government to give them a little more time

There are many freedom fighters who had participated in the State People's movements in the ex-State areas and they are in acute financial difficulties. Some of them have not applied; they should be given more time to apply. Are they not entitled to get this pension? In Orissa there are about 10,000 such political freedom fighters and I do plead with the Government that they must come out with some kind of a measure in this House soon. The Government should declare in this House that they would bring forward a comprehensive Bill in the next session. I think the freedom fighters of this country will be greatly obliged But it is not a question of obligation; it is our duty to the freedom fighters in the country that Parliament in 1971 redeems its pledge to the freedom fighters in the country. With these remarks, I support the Bill.

SHRI SAMAR GUHA (Contai): It is not only a sad commentary, but also a shameful commentary on the part of the Government and also on the part of all of us that even after 2½ decades we have not been able to discharge our minimum elementary obligation to the freedom fighters of our country. The edifice of our freedom has been built on the blood of the martyrs. We have not been able, even now, to show what is absolutely required of a dignified nation, a free nation, to show honour to our freedom fighters, to give them a place of glory in the history of our national freedom. Today in the background of the national revolution in Bangla Desh where the fighters for independence have embraced martyrdom, it is more than ever necessary that we lose no time to discharge what I have referred to as the elementary national obligation to our freedom fighters.

I have had a talk with the President of the Bangla Desh Government, the Prime Minister and the Home Minister You will be pleased to know that even before they got power in their hands, even before they had shifted to Dacca the capital, they have drawn up a list of names of the martyrs and freedom fighters and a plan how to decorate them and look after the families of those who have sacrificed their lives and those who have been incapacitated while participating in the freedom struggle and how they will take care for their future. They have told us that they were going to raise monuments in Chhittagong where Surya Sen, the great leader of the Chittagong Raid Case had laid down his life. They are going to erect monuments in the jails of Bangla Desh for the martyrs of the pre-independent days. Bangla Desh was really Centre of the revolutionary movement in those days; it was from Dacca that revolutionary inspiration radiated all over the country. They are going to honour not only the revolutionaries and freedom fighters and the young brilliant boys of the Mukti Bahini but even the old revolutions who were a source of inspiration—Surya Sen, Benoy Bose, Dinesh Gupta, AnilDas, Pritilata Waddy, who laid down their lives for the freedom of our country. They are remembering them but it requires us to remind the Government and remind ourselves, after 2½ decades of our freedom that we have to honour our freedom fighters and we haveto look after them. How many of

them are living in what pathetic conditions, you may not know. But the old revolutionaries were very dignified. I know that many of them will not beg of you for Rs. 50 or Rs. 100, but it is our sacred duty to save their lives. I know that in Bengal and other States there are old revolutionaries, aged 80 or even 85, with nobody in this world to look after them. Recently a *sadan* has been built near Calcutta for some of them on the basis of private donations, not with Government help. In the last session I raised this question not once, but several times. They have nowhere to go, they have to breathe their last in a free country, for the freedom of which they have given their all, but the nation has not done anything for them, has not got even the feeling that it should look after them. How will they breathe their last in peace?

Recently I have written several letters to Shri K.C. Pant Many of the revolutionaries in the T.B. hospitals, in a miserable condition, asking for some help from the Government. What is the Government giving? A lump sum allocation of Rs. 250 or Rs. 500, not more than that. What can they do with it? They can do nothing with this meagre help.

You probably know that the Government has given something to the Andaman prisoners, but that also was done after a long effort in this house. Their number is not more than 300. Again, you will remember that a Committee of this House was constituted to go to the Andamans and see how the Andaman Cellular Jail can be preserved, how a monument can be raised there, how we can honour our revolutionaries and martyrs. It was agreed that Netaji Subhas Bose, raised the first flag of Indian freedom, in Andamans. We submitted a report to the Government. Three years have passed, but the Government has not taken any step whatsoever, and we do not even know whether they are contemplating taking any step at all. . The Government agreed to give some help to those who had been for five years in the Andamans, but now they have extended it to anybody who had been in the Andamans.

Somebody was saying that the Bill was not well drafted, but in this House in the last two years there were innumerable questions. When I raised the question and said that many of the revolutionaries who were 80 or 85 years old would be no more because the Government was not discharging its obligation towards them, the Prime Minister said that they would not be allowed to die. One year passed, and again I raised the question, and the reply was that it was under the consideration of the Government. How long will it be under the consideration of the Government? Already two and a half decades have passed, and it is shame on all of us who enjoy the benefits of freedom that we have not been able to discharge our duty towards the freedom fighters as a result of whose sacrifices we are enjoying this freedom. It is a national disgrace, I should say, that we have not been able to honour them or look after them.

There are three categories of freedom fighters, those who followed the Gandhian line, those who followed the revolutionary course and those who joined Netaji in the INA movement. You have done nothing for them. The Government has said on some occasions that the State Governments are giving some help to the freedom fighters. Again, I do not know how the Government uttered the word "help", because the help that is given is not more than Rs. 50 and very often much less, and only in a few cases these pensions are given to the freedom fighters. This is the honour that you are showing to the freedom fighters.

This Government dares to say that we are giving help to the freedom-fighters. Every year we are giving so many decorations—Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Bharat Ratna and so on —to so many people but during the last 25 years, the Government did not give any decoration or show honour to any of the freedom-fighters. Nomonument has been raised anywhere. It should have been the duty of the Government to raise monuments in each metropolis of India—Calcutta, Bombay, Madras and Delhi

[Shri Samar Guha]

—in honour of our martyrs and freedom fighters It is a very good sign that the whole House unanimously cutting across party barriers, like a patriot or nationalist who feels that we are indebted to our freedom-fighter of Azad Hind Revolution, has expressed the view that we have to discharge our national duty Today I want a categorical assurance from Government as to what they are going to do, how long more they are going to take to come to a decision in this matter Let the Government say that they are thinking of doing something and at least let a committee of this House be formed to make suitable recommendations to Government It is a question of giving not aid but *Vir Pronam* to our freedom-fighters to maintain their honour The Government should categorically say what steps they are going to take and when Otherwise it will be an act not only of ingratitude but of betrayal of our freedom-fighters on whose blood the edifice of our freedom has been built

SHRI B S MURTHY (Amalapuram) Sir, today the nation is being tossed on the waves of jubilation because of the excellent work done by our armed forces in combination with the Mukti Bahini At a time like this, we should remember what happened in the years gone by and how many young patriot wanted to face any difficulty whatsoever to make India free I find that Government is willing to concede the principle, adumbrated in the Bill but I do not know why they could not make up their mind even though this Bill has been before them for the last 6 or 7 months As a matter of fact the freedom fighters are the basic persons who have constructed a new India Therefore there should be monuments erected everywhere in the country It may be left to the villagers to construct their own monuments n memory of the freedom-fighters of those villages so that posterity may remember them But it is the duty of the Government to see that at the State and district level and if possible at the taluk level monuments are erected so that our children may know how our people had fought against the British imperialism to see that the British yoke is removed from India

12 25 hrs

MR SPEAKER *In the Chair*

These monuments are very essential so that posterity will know the patriotic persons who sacrificed everything and laid down their lives to achieve freedom

I would not like to say that the Government had not done much The State Governments have also come forward to help the freedom fighters But that is a very petty and parsimonious help Each man has to go and get a certificate from some Congress organisation and approach the Collector or the Tahsildar as the case may be and go there umpteen times in order to get himself registered as a freedom fighter The word political sufferer must be removed from the records of Government The world 'freedom fighter is a proper word that should be given to those patriotic persons who sacrificed everything and died for winning the freedom of the country

Another point that I would like to place before the House is this They say that they want to give political pension It will be very wrong and derogatory to the spirit exhibited by the revolutionaries to say that we are giving them a pension It must be an honorarium freely given and gracefully accepted Both the Central Government and the State Governments must see that before we celebrate Silver Jubilee of our Independence next year a full list of the freedom fighters is drawn up and their names displayed at important places

Lastly I would like to know whether the Government is accepting this Bill as it is or whether they are going to refer the Bill to a Select Committee or whether they are going to bring forward another Bill incorporating the principles adumbrated in Mr Saksena s Bill so that there will be no difficulty in future

One thing I must say that the whole house is behind this Bill There is no difference of opinion on party affiliations Most of them have been freedom fighters There-

fore, the Government should respect the wishes of the House and see that either this Bill is recast or a new Bill is brought before the House so that the obligation of the nation to these martyres is fulfilled

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली · (टिहरी-गढ़वाल) अध्यक्ष महोदय मैं श्री शिब्बन लाल सक्सेना जी के इस बिल का समर्थन करता हूं और महसूस करता हूं कि यह एक बहुत सामयिक बिल है। यद्यपि इसमें कुछ दोष हैं फिर भी मैं समझता हूं चूंकि हमारी आजादी की सिल्वर जुबली 1972 में मनाई जाने वाली है इसलिए यह अच्छा होगा कि इस बिल को ध्यान में रखकर भारत सरकार कुछ ठोस कदम उठाये। मेरा निवेदन यह है कि भारत सरकार को एक तो फ्रीडम फाइटर्स की हिस्ट्री इस अवधि में तैयार करनी चाहिये। दूसरा कदम जो उठाया जा सकता है वह यह कि फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपनी जान दी है फांसी के तख्ते पर चढ़े हैं जिन्होंने दूसरे देशों में जाकर अपनी जानें दी हैं उन लोगों के उन स्थानों पर मेमोरियल्स बनाये जायें। इसके अलावा सारे प्रदेश सरकारों को आदेश प्राप्त होने चाहिए

MR SPEAKER You will continue later on The Prime Minister will make a statement now ——

12 29 hrs

STATEMENT RE INDIA'S DECISION TO CEASE OPERATIONS FROM 20 00 HRS ON THE 17TH DECEMBER, 1971 ON ALL FRONTS IN THE WESTERN SECTOR

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTRONICS, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) Mr Speaker, Sir, on March 31, 1971 six days after the great upheavel in Bangla Desh, I had the honour to move a Resolution in this House

I said then that India's permanent interest in peace and our commitment to uphold and defend human rights demanded the immediate cessation of the use of force and of the massacre of defenceless people of Bangla Desh. I had called upon all peoples and Governments to take urgent and constructive steps to prevail upon the Government of Pakistan to immediately end the systematic decimation of a people I had concluded my statement by expressing the profound conviction of this House that the historic upsurge of the 75 million people of East Bengal would triumph We also gave an assurance that their struggle and sacrifice would receive the whole-hearted sympathy and support of the people of India Today, the pledge we then made together in this House and in the country stands redeemed

It is natural that the people of India should be elated We can also understand the great rejoicing of the people of Bangla Desh I share the elation and the joy But as the Gita says neither joy nor sorrow should tilt the balance of our equanimity or blur our vision of the future

All those who have borne arms all those who have been involved in the planning and direction of the operations, all the people of India who have responded so generously, these are to be thanked and congratulated

It is a victory but a victory not only of arms but of ideas The *Mukti Bahini* could not have fought so daringly but for its passionate urge for freedom and the establishment of a special identity of Bangla Desh Our own forces would not have been so fearless and relentless had they not been convinced of our cause

India has always stood for breadth of vision, tolerance of the points of view of others, of being in the battle yet above it.

We stand for Democracy, for Secularism and for Socialism Only this combination opens the way for full freedom, gives protection to the weaker sections and provides opportunity for the growth of different personalities

We believe that no nation can be built on concepts which are negative or which do not have meaning for all its people. Unfortunately, Pakistan has based its policies